



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

113
26/1/48

सं. 394]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 1938/आषाढ़ 27, 1919

No. 394]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 1938/ASADHA 27, 1919

इस भाग में मिले हुए संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विप संवालय

(राजपत्र विभाग)

अधिपुचवा

नई दिल्ली 18 जुलाई, 1938

संख्या 51/गैर टैरिफ/38 सीमा-शुल्क

सा. का. नि 800(घ).—(अ) केंद्रीय सरकार, साधारण खंड
अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 2 के साथ पठित
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमाशुल्क मूल्यांकन नियम, 1963
को प्रतिष्ठित करने हुए निम्नलिखित उन बातों को छोड़कर जो ऐसे
प्रतिष्ठित किए जाने के पूर्व की गई या जो जाने से नहीं गई हैं,
निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होने—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित
माल की कीमत का अद्यपारित) नियम, 1938 है।

(2) ये नियम 16 अगस्त, 1938 को प्रवृत्त होंगे।

(3) से उस आयातित माल का लागू होगा जहां सीमाशुल्क
उसके मूल्य के प्रति निर्देश से प्रभावित है।

2 परिभाषाएँ—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ
अपेक्षित नहीं है,—

(क) "विपमतात्मक मूल्य" से इन नियमों के नियम 7
के अन्तर्गत अद्यपारित मूल्य अभिप्रेत है।

(ख) "एक ही वर्ग या किस्म का माल" से ऐसा आयातित माल
अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट उद्योग या औद्योगिक
सेक्टर द्वारा उत्पादित आयातित माल के किसी समूह
या रेंज के भीतर है और इसके अंतर्गत समरूप या
वैसा ही मान भी है।

(ग) "समरूप माल" से ऐसा आयातित माल अभिप्रेत है—

(i) जो मूल्यांकित किए जाने वाले माल के रूप में,
सभी पहलुओं से, जिनके अंतर्गत भौतिक लक्षण, क्वा-
लिटी और क्यालि है, निम्नलिखित रूप में ऐसे लघु
अंशों के, जो माल के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालते हैं,
समान हैं—

- (ii) ऐसे देश में उत्पादित किया गया है जिसमें वह माल जिसको मूल्यांकित किया जा रहा है, उत्पादित किया या और;
- (iii) उसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित किया गया है जिसने उस माल को उत्पादित किया था या जहाँ कोई भी ऐसा माल उपलब्ध नहीं है, वहाँ निम्न व्यक्ति द्वारा उत्पादित किया गया है,

किन्तु इसमें ऐसा आयातित माल सम्मिलित नहीं होगा जिसमें इंजीनियरी, विकास कार्य, कला कार्य, डिजाइन कार्य, रेखांक या रेखाचित्र की, जिसे भारत में ह्रास में लिया गया था, क्रेता द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आयातित माल पर इस आयातित माल के निर्यात के लिए उत्पादन और विक्रय के संबंध में उपयोग के लिए, निःशुल्क या कम की हुई लागत पर पूरा किया गया ;

(घ) "उत्पादित" के अंतर्गत उगाया गया, विनिर्मित और खनित है,

(ङ) "वैसा ही माल" से ऐसा आयातित माल अभिप्रेत है,—

(i) जो यद्यपि सभी पहलुओं में समान नहीं है किन्तु ऐसे समान लक्षण और समान संघटक सामग्री रखता है जो उसे वही कृत्य निष्पादित करने में समर्थ बनाती है और वह ट्रेड मार्क की क्वालिटी, प्रसिद्धि और विद्यमानता का ध्यान रखते हुए मूल्यांकित किए जाने वाले माल के साथ वाणिज्यिक रूप से अंतर विनिमय है;

(ii) ऐसे देश में उत्पादित किया गया है जिसमें मूल्यांकित किया जाने वाला माल उत्पादित किया गया था ; और

(iii) उसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित किया गया है जिसने मूल्यांकित किया जाने वाला माल उत्पादित किया था या जहाँ कोई ऐसा माल उपलब्ध नहीं वहाँ निम्न व्यक्ति द्वारा उत्पादित किया गया है ;

किन्तु इसमें ऐसा आयातित माल सम्मिलित नहीं होगा जिसमें इंजीनियरी, विकास कार्य, कला कार्य, डिजाइन कार्य, रेखांक या रेखाचित्र की, जिसे भारत में ह्रास में लिया गया था, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः इस आयातित माल पर इस आयातित माल के निर्यात के लिए उत्पादन और विक्रय के संबंध में उपयोग के लिए, निःशुल्क या कम की हुई लागत पर पूरा किया गया है ;

(च) "संयवहार मूल्य" से इन नियमों के नियम 4 के अनुसार अवधारित मूल्य अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों के प्रयोजन के लिए व्यक्ति "संबंधित" केवल तभी समझे जाएंगे जब—

(i) वे एक दूसरे के कारबार के अधिकारी या निवेशक हैं ;

(ii) वे कारबार में वित्तीय रूप से मान्यता प्राप्त भागीदार हैं ;

(iii) वे निराश्रित और नियोजित हैं ;

(iv) कोई व्यक्ति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उनमें से दोनों के बकाया धर्तों अथवा शायरी के पांश प्रतिपात या अधिकार पर स्वामित्व, नियंत्रण रखता है या उन्हें धारण करता है ;

(v) उनमें से एक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दूसरे को नियंत्रित करता है ;

(vi) उनमें से दोनों प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हैं ;

(vii) वे एक साथ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं ; या

(viii) वे एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं।

स्पष्टीकरण:—I. "व्यक्ति" शब्द के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी है।

स्पष्टीकरण:—II. ऐसे व्यक्ति, जो एक दूसरे के कारबार में सहबद्ध हैं, उनमें से एक दूसरे का एक माल अधिकारी या एक माल वितरक या एक मात्र छूट प्राप्ति व्यक्ति है, जैसे भी वर्णित किया जाए, इन नियमों के प्रयोजन के लिए संबंधित समझे जाएंगे यदि वे इस उपनियम की कसौटी के भीतर आते हैं।

3. मूल्यांकन की पद्धति का अवधारण—इन नियमों के प्रयोजन के लिए:—

(i) आयातित माल का मूल्य संयवहार मूल्य होगा।

(ii) यदि मूल्य उक्त खंड (i) के उपबन्धों के अधीन अवधारित नहीं किया जा सकता है तो मूल्य इन नियमों के नियम 5 से 8 तक के माध्यम से क्रमिक रूप से कार्यवाही करके अवधारित किया जाएगा।

4. संयवहार मूल्य (1) आयातित माल का संयवहार मूल्य उस माल के लिए जब उसका भारत में निर्यात के लिए विक्रय किया गया हो, वास्तविक रूप से संवत् या संदिय मूल्य होगा, जो इन नियमों के नियम 9 के उपबन्धों के अनुसार समायोजित किया गया है।

(2) उक्त उपनियम (1) के अधीन आयातित माल का संयवहार मूल्य स्वीकार किया जाएगा ;

परन्तु यह तब जब कि :—

(क) क्रेता द्वारा माल के व्यय या उपयोग के बारे में उन निबंधनों से निम्न कोई निबंधन नहीं है जो—

(i) विधि द्वारा या भारत में लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित किए गए हैं या अपेक्षित हैं ;

(ii) ऐसे भौतिक खेप को परिलीमित करते हैं जिसमें माल का पुनः विक्रय किया जा सकेगा ; या

(iii) माल के मूल्य को सारत ; प्रभावित नहीं करते हैं ;

(ख) विक्रय या कीमत ऐसी शर्त या प्रतिकूल के अधीन नहीं है जिसके लिए मूल्यांकित किए जाने वाले माल के सम्बन्ध में मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है ;

(ग) क्रेता द्वारा माल के किसी पश्चात्पूर्ति पुनः विक्रय व्यय या उपयोग के भाग का कोई भाग प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विक्रेता को प्रदत्त नहीं होगा जब तक कि इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कोई उचित समायोजन न किया जा सकता है ; और

(घ) क्रेता और विक्रेता सम्बन्धित नहीं हैं या जहाँ क्रेता और विक्रेता सम्बन्धित हैं वहाँ संयवहार मूल्य नीचे उपनियम 3 के उपबन्धों के अधीन सीमाशुल्क के लिए स्वीकार्य है।

(3) (क) जहाँ क्रेता और विक्रेता सम्बन्धित हैं, संयवहार मूल्य स्वीकार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि आयातित माल के विक्रय की परिस्थितियों की परीक्षा यह वक्षित करती हो कि सम्बन्ध के कीमत को प्रभावित नहीं किया था।

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच विक्रय में, संयवहार मूल्य स्वीकार किया जाएगा जब कभी आयातकर्ता यह सम्प्रवक्षित करता है कि मूल्यांकित किए जाने वाले माल का घोषित मूल्य एक ही समय

पर या उसके लगभग अभिनिश्चित निम्नलिखित मूल्यांकनों में से किसी एक के स्पष्ट रूप से करीब है:—

- (i) भारत में प्रसम्भित क्रेताओं की विक्रय में समरूप माल या वैसे ही माल का संव्यवहार मूल्य;
- (ii) समरूप माल या वैसे ही माल के लिए निगमनात्मक मूल्य;

परन्तु तुलना के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्यों को लागू करने में वाणिज्यिक स्तरों, परिमाण स्तरों, इन नियमों के नियम 9 के उपबंधों के अनुसार समायोजनों और उन विक्रयों में जिनसे वह बड़े और और क्रेता सम्बन्धित नहीं हैं, विक्रेता द्वारा उपगत लागत में सम्प्रविष्ट अक्षर का सम्यक ध्यान रखा जाएगा;

(ग) इस उपनियम के खण्ड (द) के उपबंधों के अधीन प्रति मूल्य स्थापित नहीं किए जाएंगे।

6. समरूप माल का संव्यवहार मूल्य:—

(1) (क) इस नियम के नियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयातित माल का मूल्य भारत में निर्यात के लिए विक्रय किए गए और माल के मूल्यांकित किए जाने के समय पर या उसके लगभग आयातित समरूप माल का संव्यवहार मूल्य होगा।

(ख) इन नियमों के लागू करने में समान वाणिज्यिक स्तर पर विक्रय में, समरूप माल के संव्यवहार मूल्य और भारत: वही उसी परिमाण को, जो प्रभावित किए जाने वाले माल का है, में आयातित किया जाएगा;

(ग) जहाँ इस नियम के उपनियम (1) के खण्ड (क) में निरिष्ट कोई विक्रय पाया जाता है, वहाँ निम्न वाणिज्यिक स्तर पर या निम्न परिमाणों में या दोनों में विक्रय किए गए समरूप माल के संव्यवहार मूल्य का, जो वाणिज्यिक स्तर या परिमाण या दोनों के कारण अक्षर का ध्यान रखने के लिए समायोजित किया गया है, उपयोग किया जाएगा;

परन्तु यह कि ऐसे समायोजन ऐसे सम्प्रविष्ट साम्य के आधार पर किये जाएंगे, जो स्पष्ट रूप से समायोजनों की उपयुक्तता और निश्चितता को स्थापित करते हैं, चाहे ऐसे समायोजनों के कारण मूल्य में वृद्धि होती हो या कमी होती हो।

(2) जहाँ इन नियमों के नियम 9 के उपनियम (2) में निरिष्ट लागत और प्रभार समरूप माल के संव्यवहार मूल्य में सम्मिलित हैं वहाँ समायोजन किया जाएगा यदि दूरियों और परिवहन के साधनों में अक्षर से उत्पन्न होने वाले प्रश्न में मूल्यांकित किए जाने वाले माल और समरूप माल के बीच लागत और प्रभार में महत्वपूर्ण अन्तर है।

(3) इन नियमों को लागू करने में यदि समरूप माल का एक से अधिक संव्यवहार मूल्य पाया जाए तो ऐसे निम्नतम मूल्य का आयातित माल का मूल्य अवधारित करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

6. समरूप माल का संव्यवहार मूल्य:—

(1) इन नियमों के नियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयातित माल का मूल्य भारत को निर्यात के लिए विक्रय किए गए और माल को मूल्यांकित किए जाने समय या उसके लगभग समय पर समान माल का संव्यवहार मूल्य होगा।

(2) इन नियमों के नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) और (ग) और उपनियम (2) और उपनियम (2)

(3) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, समान माल के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

7. निगमनात्मक मूल्य:—

(1) इन नियमों के नियम 3 उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि मूल्यांकित किए जाने वाले या मन्त्र या वैसे ही आयातित माल का भारत में उसी वर्ग में, जैसे कि उसका उस समय या उसके लगभग समय पर जब मूल्य के अवधारण के लिए घोषणा की जाती है, आयात किया जाता है, विक्रय किया जाता है तो आयातित माल का मूल्य उस यूनिट कीमत पर आधारित होगा जिस पर आयातित माल या समरूप अवस्था समान आयातित माल का सर्वाधिक समुच्चय परिमाण में उन व्यक्तियों को जो भारत में विक्रेताओं से सम्बन्धित नहीं हैं, निम्नलिखित कटौतियाँ अधीन रहते हुए, विक्रय किया गया है:—

(i) या तो उसी वर्ग या किस्म के आयातित माल का भारत में विक्रय के सम्बन्ध में लोगों को साधारणतया धन्य के लिए या तो कमीशन का साधारणतया संशय किया गया है या संशय किए जाने के लिए तय पाया गया है या साधारणतया परिवर्तन किया गया है;

(ii) भारत में उपगत किए गए परिवहन और बीमा के समस्त खर्च और सहज खर्च;

(iii) सीमाशुल्क और अन्य कर माल के आयात किए जाने या विक्रय के कारण भारत में संवेद्य हैं।

(2) यदि न तो आयातित माल का, न समरूप अवस्था वैसे ही आयातित माल का मूल्यांकित किए जाने वाले माल का आयात के समय पर या उसके लगभग विक्रय किया गया है तो आयातित माल का मूल्य, इस नियम के उपनियम (1) के उपबंधों के अन्वया अधीन रहते हुए, उस यूनिट कीमत पर आधारित होगा जिस पर आयातित माल या समरूप या वैसे ही आयातित माल का भारत में आयात के पश्चात् शीघ्रतम सारीख पर किन्तु ऐसे आयात के पश्चात नब्बे दिन की समाप्ति के पूर्व विक्रय किया जाता है।

(3) (क) यदि न तो आयातित माल का समरूप या वैसे ही आयातित माल का भारत में आयात किए गए खर में शर्त के साथ विक्रय किया जाता है तो मूल्य उस यूनिट कीमत पर आधारित होगा जिन पर आयातित माल का उस पर प्राप्ति प्रक्रिया करने के पश्चात् सर्वाधिक समुच्चय परिमाण में उन व्यक्तियों को विक्रय किया जाता है जो भारत में विक्रेता से सम्बन्धित नहीं हैं:

(ख) ऐसे अवधारण में प्रक्रिया करके जोड़े गए मूल्य के लिए और इस नियम के उपनियम (1) के मर (i) से (iii) तक में उपबंधित की गई कटौतियों के लिए सम्यक भोक्त हो जाएगी।

(3) (क) यदि न तो आयातित माल का समरूप या वैसे ही आयातित माल का भारत में आयात किए गए खर में शर्त के साथ विक्रय किया जाता है तो मूल्य उस यूनिट कीमत पर आधारित होगा जिन पर आयातित माल का उस पर प्राप्ति प्रक्रिया करने के पश्चात् सर्वाधिक समुच्चय परिमाण में उन व्यक्तियों को विक्रय किया जाता है जो भारत में विक्रेता से सम्बन्धित नहीं हैं:

(ख) ऐसे अवधारण में प्रक्रिया करके जोड़े गए मूल्य के लिए और इस नियम के उपनियम (1) के मर (i) से (iii) तक में उपबंधित की गई कटौतियों के लिए सम्यक भोक्त हो जाएगी।

8. अविश्लेष्य पद्धति:—

(1) इन नियमों के नियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहाँ आयातित माल का मूल्य किसी पूर्ववर्ती नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अवधारित नहीं किया जा सकता है, वहाँ मूल्य का अवधारण इन नियमों के साधारण उपबंधों और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)

की धारा 14 की उपधारा (1) से संगत मुक्तियुक्त माधनों का उपयोग करके और भारत में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

- (2) कोई मूल्य इन नियमों के उपबंधों के प्रदान निम्नलिखित के आधार पर अवधारित नहीं किया जाएगा:—

- (i) भारत में उत्पादित माल का भारत में विक्रय मूल्य ;
(ii) कोई पद्धति जो दो आर्थिक मूल्यों में से उच्चतम के सीमाशुल्क प्रयोजनों के स्वीकार किए जाने के लिए उपबंधित करती है ;

- (iii) निर्यात के देश के देशीय बाजार में माल की कीमत ;

- (iv) भारत से भिन्न देश की निर्यात के लिए माल की कीमत ;

- (v) न्यूनतम सीमाशुल्क ; या

(भनमाने अथवा काल्पनिक मूल्य ।

9. खर्च और सेवाएं—

- (1) संव्यवहार मूल्य का अवधारण करने में प्रायतित माल के लिए वास्तविक में संदेय या संदेय कीमत के लिए निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:—

(क) निम्नलिखित खर्च और सेवाएं उस सीमा तक जहां तक वे केला द्वारा उभराने की जाती हैं किन्तु प्रायतित माल के लिए वास्तव में संदेय या संदेय कीमत में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात्—

- (i) कमीशन और दलाली, कय करने के कमीशन को छोड़कर ;

- (ii) प्राधानों का खर्च जो प्रत्यक्ष माल के साथ सीमाशुल्क प्रयोजनों के लिए एक माना जाएगा ;

- (iii) पैक करने का खर्च चाहे वह श्रमिक के लिए लिए हो या सामग्री के लिए ;

(ख) निम्नलिखित माल और सेवाओं का जहां केला द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निशुल्क या कम किए हुए खर्च पर प्रायतित माल के निर्यात के लिए उत्पादन और विक्रय के सम्बन्ध में उपयोग के लिए प्रदाय किया गया है, समुचित रूप में प्रभावित मूल्य उस सीमा तक जहां तक कि ऐसे मूल्य वास्तव में संदेय या संदेय कीमत में सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात्—

- (i) प्रायतित माल में नियमित सामग्री, संघटक पुर्जें और बैसी ही मर्चे ;

- (ii) औजार, डाई, सांचे और बैसी ही मर्चे जिनका प्रायतित माल के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ;

- (iii) प्रायतित माल के उत्पादन में उपयोग की गई सामग्री ;

- (iv) इंजीनियरी, विकास, कला कार्य, डिजाइन कार्य और रेखांक और रेखांकित जो भारत से प्रत्यक्ष हाथ में लिए गए हैं और प्रायतित माल के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं।

(ग) प्रायतित माल के सम्बन्धित रायल्टी और श्रुतिशक्ति फीम जिसकी कि केला में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः मूल्यांकित किए जाने वाले माल के विक्रय की शर्त के रूप में उस सीमा तक जहां तक कि ऐसी रायल्टी और फीम वास्तव में संदेय किए गए या संदेय कीमत में सम्मिलित नहीं हैं, संदेय करने की श्रेष्ठा की गई है ;

(घ) प्रायतित माल के किसी पश्चात्तर्ती पुनः विक्रय, व्ययन या उपयोग के प्रागामों के किसी भाग का मूल्य जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः केला को प्रोद्भूत होता है ;

(ङ) अन्य सभी सहाय, जो प्रायतित माल के विक्रय की शर्त के रूप में केला द्वारा विक्रेता को या केला द्वारा सीधे पक्षकार को विक्रेता की किसी बाधना की पूर्ण करने के लिए उस सीमा तक जहां तक कि ऐसा संदेय वास्तव में संदेय अथवा संदेय कीमत में सम्मिलित नहीं हैं वास्तव में किए गए या किए जाने वाले हैं।

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (1क) तथा इन नियमों के प्रयोजनों के लिए प्रायतित माल का मूल्य प्रायत के समय और स्थान पर परिदान के लिए ऐसा माल का मूल्य होगा और उनके अन्तर्गत निम्नलिखित होगा:—

(क) प्रायतित माल के प्रायत के स्थान को परिवहन का खर्च ;

(ख) प्रायत के स्थान पर प्रायतित माल के परिदान में सहबद्ध लागने उत्पन्न और उठाई घटाई के प्रभार ;

(ग) बीमा का खर्च, परन्तु यह और कि वायु मार्ग द्वारा प्रायतित किए जाने वाले माल की वशा में उक्त खण्ड (क), (ख) और (ग) में निविष्ट खर्च और प्रभार—

(1) जहां ऐसा खर्च और प्रभार अभिनिश्चय है, वहां वे ऐसे माल के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(2) जहां ऐसा खर्च और प्रभार अभिनिश्चय नहीं है, वहां ऐसे खर्च और प्रभार ऐसे माल के पोतपर्यन्त निशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत होंगे ;

परन्तु यह और कि वायु मार्ग से अथवा प्रायत किए गए माल की वशा में और उक्त खण्ड (क), (ख) और (ग) में निविष्ट वास्तविक खर्च और प्रभार अभिनिश्चय न होने की वशा में ऐसे खर्च और प्रभार जो ऐसे माल के पोतपर्यन्त निशुल्क मूल्य के 25 प्रतिशत होंगे।

(3) वास्तव में सत्य की गई या संदेय कीमत में बुद्धि इन नियमों के अधीन श्रुतिपत्र और परिमाण्य सामग्री के आधार पर की जाएगी।

(4) इस नियम में उपबंधित के सिवाय प्रायतित माल के मूल्य का अवधारण करने में वास्तव में संदेय की गई या संदेय कीमत में कोई बुद्धि नहीं की जाएगी।

10. प्रायतकर्ता द्वारा घोषणा:—

(1) प्रायतकर्ता या उसका अधिकारी:—

(क) प्रायतित माल के मूल्य से सम्बन्धित पुनः और शर्तों को प्रकट करने हुए घोषणा करेगा, और

(क) कोई अन्य विवरण, जनकारी या दस्तावेज जो इन नियमों के अधीन प्रायश्चित्त भाल के मूल्य का अधिधारण करने के लिए सिमाशुल्क अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाए, देगा।

(2) इन नियमों में अन्तर्निहित किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उचित सिमाशुल्क अधिकारी के मूल्यांकन प्रयोजन के लिए पर्याप्त किए गए किसी विवरण, जनकारी, दस्तावेज या घोषणा के अन्वय या सही होने के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के अधिधारण को निर्बन्धित करती है या प्रभावित करती है।

(3) सम्पन्नरण भारत और अधिवाहन से सम्बन्धित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के उपबंध ऐसे मामलों में लागू होंगे जहाँ इन नियमों के अधीन गलत योग्यता, जाने वाली विवरण या दस्तावेज दिए गए हैं।

1. विवाद का निपटारा—आयातकर्ता और भाल को मूल्यांकित करने वाले उचित सिमाशुल्क अधिकारी के बीच किसी विवाद की दशा में उनको सिमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (1) में अन्तर्निहित उपबंधों से संज्ञा रूप में गुप्तताया जाएगा।

2. निर्वचनात्मक टिप्पण—इन नियमों की अनुसूची में विनिश्चित निर्वचनात्मक टिप्पण इन नियमों के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

अनुसूची

(नियम 12 देखिए)

निर्वचनात्मक टिप्पण

साधारण टिप्पण

आधारणतया स्वकार किए गए लेखाकरण निष्ठाओं का उपयोग

1. 'साधारणतया स्वकार किए गए लेखाकरण निष्ठाओं' किसी विशिष्ट समय पर देश के भीतर मायता प्राप्त सर्वसम्पन्न या महत्वपूर्ण प्राधिकार पूर्ण समर्थन को इस बारे में विनिश्चित करते हैं कि कौन से अधिक श्रोता और व्यवस्थाओं को आस्तियों और दायित्वों के रूप में अभिलिखित किया जाना चाहिए, आस्तियों और दायित्वों में कौन से परिवर्तन अभिलिखित किए जाने चाहिए, कैसे आस्तियों और दायित्वों तथा उनके परिवर्तनों को मापा जाना चाहिए, कौनसी जानकारी प्रकट की जानी चाहिए और वह कैसे प्रकट की जानी चाहिए और कौनसी वित्तीय विवरण तैयार किया जाना चाहिए। ये मानक साधारणतया लागू किए जाने वाले व्योमकार पद्धति और प्रक्रिया के विस्तृत वर्णन का हो सकते हैं।

नियमों के बारे में टिप्पण

नियम 2 का टिप्पण

इन नियमों के प्रयोजनों के लिए नियम 2 (2)(v) में कोई व्यक्ति दूसरे का नियंत्रित करने वाला समझा जाएगा जब पहले का अधिक रूप से या क्रियात्मक रूप से बाह्य वाले के उपर निर्बंधन या निर्देश का प्रयोग करने की स्थिति में है।

नियम 4 का टिप्पण

वास्तव में संश्ल की गई या संश्ल कीमत

वास्तव में संश्ल की गई या संश्ल कीमत क्रेता द्वारा आयातित भाल के लिए विक्रेता को या उसके लाभ के लिए किया गया या किया जाने वाला पूर्ण संश्ल है। संश्ल के बारे में यह आवश्यक नहीं है कि वह

धन के अंतरण का रूप ले। संश्ल अन्तःदेशी या पर-देशी लिखतों के रूप में किया जा सकता है। संश्ल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष संश्ल का एक उदाहरण विक्रेता द्वारा देय भुगतान, चाहे पूर्णतः या अंशतः क्रेता द्वारा परिनिधारेण होगा।

क्रेता द्वारा अपने लिखे दाय के लिए गए क्रियाकलाप, उनसे भिन्न जिनके लिए नियम 9 में समायोजन का उपबंध किया गया है, क्रेता को अप्रत्यक्ष संश्ल नहीं समझे गए हैं। क्रेता से विक्रेता के लिए लाभ के रूप में भाने गए हों। अतः ऐसे क्रियाकलापों का स्वयं आयातित भाल के मूल्य का अधिधारण करने में वास्तव में संश्ल की गई या संश्ल कीमत में जोड़ा नहीं जाएगा।

आयातित भाल के मूल्य में निम्नलिखित प्रभाव या खर्च सम्मिलित नहीं होंगे परंतु यह तब जबकि वे आयात किए गए भाल के लिए वास्तव में संश्ल या संश्ल कीमत से मुक्ति हो:

(क) गतिमान, परिवर्तमान, संयोजन, रख-रखाव या तकनीकी सहायता के लिए प्रभार जो आयात के पश्चात् ऐसे आयातित भाल के संबंध में की गई हो जैसे औद्योगिक संयंत्र मशीनरी या उपकरण।

(ख) आयात के पश्चात् परिवहन का खर्च,

(ग) भारत में शुल्क और कर।

वास्तव में संश्ल की गई या संश्ल कीमत आयातित भाल के लिए कीमत को निश्चित करती है। इसी प्रकार क्रेता से विक्रेता को ऐसे लाभ या अन्य संश्लों की गति, जो आयातित भाल से संबंधित नहीं है, सिमाशुल्क मूल्य का भाग नहीं है।

नियम 4(2)(क)(iii)

ऐसे निबंधनों, में जो वास्तव में संश्ल या संश्ल कीमत को असंश्ल नहीं करेगा, वे निबंधन हैं जो भाल के मूल्य को भारत प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसे निबंधनों का उदाहरण वह मामला होगा जहाँ कोई विक्रेता किसी मोटर गाड़ियों के क्रेता से यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसी नियत तारीख के पूर्व जो नमूना वर्ष के आरम्भ का प्रतिनिधित्व करती है, मोटर गाड़ियों का बिक्रय न करे या उन्हें प्रदर्शित न करे।

नियम 4(2)(ख)

यदि विक्रेता या कीमत किसी ऐसी शर्त या प्रतिफल के अधीन रहने लगे हैं जिसके लिए कोई मूल्य मूल्यांकित किए जाने वाले भाल के संबंध में अधिधारित नहीं किया जा सकता है तो संश्लधार मूल्य सिमाशुल्क के प्रयोजनों के लिए स्विकार्य नहीं होगा। इसके कुछ उदाहरणों में निम्नलिखित हैं:-

(क) विक्रेता आयातित भाल की कीमत इस शर्त पर स्थापित करता है कि क्रेता अन्य भाल का भी विनिश्चित परिमाणों में क्रय करेगा।

(ख) आयातित भाल की कीमत उस कामन या उप-कीमतों पर निर्भर है जिस/जिन पर आयातित भाल का क्रेता आयातित भाल के विक्रेता को अन्य भाल का बिक्रय करना है।

(ग) कीमत संश्ल के ऐसे रूप के आधार पर स्थापित की गई है जो आयातित भाल के लिए बाह्य जैसे जहाँ आयातित भाल अर्थ परिकल्पित भाल है जिसकी विक्रेता द्वारा इस शर्त पर व्यवस्था की गई है कि वह परिकल्पित भाल का विनिश्चित परिमाण प्राप्त करेगा।

तथापि आयातित माल के उत्पादन या विपणन से संबंधित शर्तें या प्रतिभूत का परिणामों संव्यवहार मूल्य का प्रतिक्षण नहीं होगा। उदाहरण के लिए इस तथ्य का कि विज्ञेता को भारत में हाथ में लिए गए रेखांक और इन्फोमिचरी देता है, परिणाम यह नहीं होगा कि नियम 4 के प्रयो-जनों के लिए संव्यवहार मूल्य की प्रवर्धन कर दिया जाए। इसी प्रकार यदि केता अपने लेखे आयातित माल के विपणन से संबंधित क्रियाकलाप हाथ में लेता है, चाहे वे केता के साथ कारर द्वारा हो, उन क्रियाकलापों का मूल्य आयातित माल के मूल्य का भाग नहीं होगा और न ऐसे क्रियाक-लाप का परिणाम संव्यवहार मूल्य का प्रवर्धन करना होगा।

नियम 4(3)

1. नियम 4(3)(क) और नियम 4(3)(ख) किसी संव्यवहार मूल्य की स्वीकार्यता स्थापित करने के विभिन्न साधनों का उपबंध करते हैं।

2. नियम 4(3)(क) उपबंध करता है कि जहां केता और विज्ञेता संबंधित हैं, वहां विज्ञेता के शर्तों और की परिस्थितियों की परीक्षा की जाएगी और संव्यवहार मूल्य आयातित माल के मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि संबंध कीमत पर प्रभाव न डालता हो। यह प्राशयित नहीं है कि उन सभी मामलों में जहां केता और विज्ञेता संबंधित हैं परिस्थितियों की परीक्षा की जानी चाहिए। ऐसी परीक्षा की केवल तभी आवश्यकता होगी जहां कीमत की स्वीकार्यता के बारे में कोई संदेह न हो, वहां यह आयातकर्ता से और जानकारी के लिए अनुरोध किए बिना स्वीकार की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए जहां सीमाशुल्क के उचित अधिकारी ने पहले ही संबंध की परीक्षा कर ली हो या उसके पास केता और विज्ञेता से संबंधित अपरिहार जानकारी हो और उनका पहले से ही ऐसी परीक्षा या जानकारी से समाधान हो गया हो कि संबंध में कीमत को प्रभावित नहीं किया है।

3. जहां सीमाशुल्क का उचित अधिकारी और जांच किए बिना संव्यवहार मूल्य स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जहां उसे आयातकर्ता को ऐसी और अपरिहार जानकारी का जो उसे विज्ञेता के शर्तों और की परिस्थितियों की परीक्षा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, प्रदाय करने के लिए अवसर देना चाहिए। इस संदर्भ में, सीमा-शुल्क के सम्बन्धित अधिकारी को यह अवसरण करने के लिए कि मूल्य पर संबंध का प्रभाव पड़ा है या नहीं; व्यवहार के सुसंगत पक्षों का, जिसके अंतर्गत यह पद्धति भी है जिससे केता और विज्ञेता अपने वाणिज्यिक संबंध स्थापित करते हैं तथा वह रीति भी है जिससे प्रत्येक मूल्य तय हुआ है परीक्षण करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए; जहां यह दिखाया सकता है कि केता और विज्ञेता, यद्यपि ये नियम 2(2) के उपबंधों के अधीन संबंध हैं, इस प्रकार से एक दूसरे से व्यव-विक्रय करते हैं मानों वे संबंधित नहीं हैं तो इस से यह प्रकट होगा कि मूल्य पर संबंध का प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके उदाहरण के रूप में, यदि मूल्य प्रत्येक उद्योग की सामान्यतः मूल्य निर्धारण प्रथा से ग्रथता उस रीति से सुसंगत पद्धति द्वारा तब हुआ है जिस रीति से विज्ञेता ऐसे केताओं के साथ जो उसके संबंधित नहीं हैं, विक्रयों के लिए मूल्य तय करता है और इससे यह प्रकट होगा कि मूल्य पर संबंध का प्रभाव नहीं पड़ा है। एक और उदाहरण के रूप में, जहां यह दर्शाया जाता है कि मूल्य सब लाभों तथा ऐसे लाभ की, जो एक ही वर्ग या किस्म के माल के विक्रय में एक प्रतिनिधिकालावधि के दौरान वसूल किए गए फर्म के समग्र लाभ का घटक है, वसूली निर्निश्चित करने के लिए पर्याप्त है तो इससे यह प्रकट होगा कि मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

4. नियम 4(3) (ख) आयातकर्ता को यह प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है कि संव्यवहार मूल्य सीमा-शुल्क के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पहले ही स्वीकृत "परीक्षण" मूल्य के चनिष्ठ रूप से निकट है और नियम 4 के उपबंधों के अर्थात् स्वीकार्य है। जहां नियम 4(3) (ख) के

अधीन परीक्षण खरा उत्तरता है वहां नियम 3(क) के अधीन प्रभाव के प्रश्न का जवाब करना आवश्यक नहीं है। यदि सीमा-शुल्क के सम्बन्धित अधिकारी के पास, चाहे कोई स्वतंत्र जांच किए बिना यह समाधान कर लेने के लिए पर्याप्त जानकारी है कि नियम 4(3) (ख) में उपबंधित परीक्षणों में से कोई खरा उत्तरता है तो उसके लिए आयातकर्ता से यह प्रकट करने की अपेक्षा करने का कोई कारण नहीं है कि परीक्षण खरा उत्तर सकता है। नियम 4(3) (ख) में पद "प्रसंबन्धित केता" से ऐसे केता अभिप्रेत हैं जो किसी विनिष्ठ मामले में विज्ञेता से संबंधित नहीं हैं।

नियम 4(3)(ख)

यह अवसरण करने के लिए कि एक मूल्य किसी आय मूल्य में "चनिष्ठ रूप से निकट" है या नहीं, अनेक बातों पर विचार करना होगा। इन बातों में आयातित माल की प्रकृति, स्वयं उद्योग की प्रकृति, वह मौसम जिसमें माल का आयात किया जाता है, और यह बात भी है कि मूल्यों में अंतर वाणिज्यिक रूप से ध्यान देने योग्य है या नहीं। क्योंकि यह बातें अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होंगी अतः कोई एक समान मानक, जैसे निश्चित प्रतिशत, हर मामले में लागू करना असंभव होगा। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे मामले में जिसमें एक प्रकार का माल अंतर्बन्धित है, मूल्य में साधारण सा अंतर प्रवर्धन हो सकता है जबकि किसी अन्य मामले में, जिसमें कि किसी अन्य प्रकार का माल अंतर्बन्धित है, यह अव-धारण करने के लिए कि संव्यवहार मूल्य नियम 4(3)(ख) में अपबन्धित "परीक्षण" मूल्यों से चनिष्ठ रूप में निकट है, एक बड़ा अंतर भी स्वीकार्य हो सकता है।

नियम 5 के बारे में टिप्पण:

1. नियम 5 को लागू करने में, सीमा-शुल्क का सम्बन्धित अधिकारी, जहां भी संभव है, एक ही वाणिज्यिक स्तर पर और तात्त्विक रूप से एक ही मात्रा में एक समान माल के विक्रय का, माल का मूल्यांकन करने में प्रयोग करेगा। जहां ऐसा कोई विक्रय नहीं पाया जाता है वहां निम्न-लिखित तीस वशाओं में से किसी एक दशा में होने वाले उत्तमान माल के विक्रय का प्रयोग किया जा सकता है:

(क) एक ही वाणिज्यिक स्तर पर किन्तु विभिन्न मात्राओं का कोई विक्रय;

(ख) विभिन्न वाणिज्यिक स्तर पर किन्तु वास्तविक रूप से समान मात्राओं का कोई विक्रय; या

(ग) विभिन्न वाणिज्यिक स्तर पर कोई विक्रय जिसमें मात्राएं विभिन्न हैं।

2. इन तीन वशाओं में से किसी के अन्तर्गत कोई विक्रय मिलने पर यथास्थित निम्नलिखित के लिए समायोजन किए जाएंगे—

(क) केवल मात्रा संबंधी बातें;

(ख) केवल वाणिज्यिक स्तर संबंधी बातें, या

(ग) दोनों बातें, अर्थात् वाणिज्यिक स्तर और मात्रा।

3. नियम 5 के प्रयोजनों के लिए उत्तमान आयातित माल के संव्यवहार मूल्य से नियम 5(1) (ख) और (ग) तथा नियम 5(2) में यथा अपबन्धित रूप से समायोजित मूल्य, जो नियम 4 के अधीन पहले ही स्वीकार्य किया जा चुका है, अभिप्रेत हैं।

4. विभिन्न वाणिज्यिक स्तरों या विभिन्न मात्राओं का कारण समायोजन की एक शर्त यह है कि ऐसा समायोजन, चाहे उसके कारण मूल्य में वृद्धि हो या कमी उस दर्शाये गए साधन के आधार पर की जाएगी जो समायोजन की उपयुक्तता और सत्यता को स्पष्टरूप से स्थापित करता है। उदाहरण के लिए वे विधिमार्ग मूल्य सूचियां जिनमें

विभिन्न स्तरों या विभिन्न मात्राओं के प्रतिनिर्देश से मूल्य दिए गए हों, इसके उदाहरण के रूप में, यदि मूल्यांकित किए जाने वाले आयातित माल में 10 यूनिट पीत परिवहन सामग्री है और ऐसा एक मात्र तत्समान आयातित माल, जिसका संयोजन मूल्य विद्यमान है, 500 यूनिटों के विक्रय का है और यह मान लिया जाता है कि विक्रेता ने मात्रा छूट की है तो अपेक्षित समायोजित विक्रेता की मूल्य सूची का प्राथम्य लेकर और उस मूल्य को 10 यूनिटों के विक्रय को लागू करते हुए पुरा किया जा सकता है। यदि मूल्य सूचि अन्य मात्राओं के विक्रय के द्वारा सत्य सिद्ध हो चुकी है तो ऐसी वधा में यह अपेक्षित नहीं होगा कि विक्रय 10 यूनिटों की मात्राओं में ही किया गया हो। इस प्रकार के उद्देश्यपूर्ण उपाय के अभाव में, नियम 6 के उपबन्धों के अधीन मूल्य का अवधारण उपयुक्त नहीं है।

नियम 6 के बारे में टिप्पण

1. नियम 6 का प्रयोग करने समय सीमा-शुल्क का समुचित अधि-कारी, जहाँ भी संभव है, समान वाणिज्यिक स्तर पर और तात्विक रूप से समान मात्राओं के वैसे ही माल के, जैसा कि मूल्यांकित किया जा रहा है विक्रय का प्रयोग करेगा। नियम 6 के प्रयोजन के लिए समान आयातित माल के संयोजन मूल्य से नियम 6(2) में यथा उपबंधित रूप से समायोजित आयातित माल का वह मूल्य अभिप्रेत है जो नियम 4 के अधीन पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है।

2. नियम 5 के टिप्पण, में अंतर्निष्ठ सभी अन्य उपबंध समान माल के संबंध में आवश्यक परिस्थितियों सहित लागू होंगे।

नियम 7 के बारे में टिप्पण :

1. "वह यूनिट मूल्य जिस पर -----माल सर्वाधिक समग्र मात्रा में विक्रय किए जाते हैं" यह से आशय है वह मूल्य जिस पर सर्वाधिक यूनिट विक्रयों में ऐसे व्यक्तियों को विक्रय किए जाते हैं जो उन व्यक्तियों से संबंधित नहीं हैं जिस से वे ऐसा माल, आयात किए जाने के पश्चात्, ऐसे प्रथम वाणिज्यिक स्तर पर क्रय करते हैं जिस पर ऐसा विक्रय होता है।

2. इसके उदाहरण के रूप में, माल का विक्रय उस मूल्य सूची से किया जाता है जो बड़ी मात्राओं में किए जाने वाले क्रयों के लिए अनुकूल यूनिट मूल्य प्रदान करती है।

विक्रय मात्रा	यूनिट मूल्य	विक्रयों की संख्या	प्रत्येक मूल्य पर विक्रय की गई कुल मात्रा
1-10 यूनिट	100	5 यूनिटों के 10 विक्रय	65
		3 यूनिटों के 5 विक्रय	
11-25 यूनिट	95	11 यूनिटों के 5 विक्रय	55
26 यूनिट से अधिक	90	30 यूनिटों का विक्रय	80
		50 यूनिटों का एक विक्रय	

एक मूल्य पर विक्रय किए गए यूनिटों की सर्वाधिक संख्या 80 है ; अतः सर्वाधिक समग्र मात्रा में यूनिट मूल्य 90 है।

3. इसके एक और उदाहरण के रूप में, मानों दो विक्रय होते हैं। पहले विक्रय में 500 यूनिटों का विक्रय 95 प्रति कनेन्टी यूनिट के मूल्य पर किया जाता है। दूसरे विक्रय में 400 यूनिटों का विक्रय 90 प्रति कनेन्टी यूनिट के मूल्य पर किया जाता है। इस उदाहरण में किसी एक निश्चित मूल्य पर विक्रय किए गए यूनिटों की सर्वाधिक संख्या 500 है, अतः सर्वाधिक समग्र मात्रा में यूनिटमूल्य 95 है।

4. तीसरा उदाहरण निम्नलिखित स्थिति का हो सकेगा जिसमें विभिन्न मात्राएँ विभिन्न मूल्यों पर विक्रय की गई हों।

(क) विक्रय

विक्रीत मात्रा	यूनिट मूल्य
40 यूनिट	100
30 यूनिट	90
15 यूनिट	100
50 यूनिट	95
25 यूनिट	105
35 यूनिट	90
5 यूनिट	100

(ख) योग

विक्रीत मात्रा का योग	यूनिट मूल्य
65	90
50	95
60	100
25	105

इस उदाहरण में किसी निश्चित मूल्य पर विक्रय किए गए यूनिटों की सर्वाधिक संख्या 85 है; अतः सर्वाधिक समग्र मात्रा में यूनिट मूल्य 90 है।

5. ऊपर दिए 1 में वर्णित अनुसार, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो आयातित माल के निर्यात के लिए उत्पादन और विक्रय के संबंध में नियम 3(1) (ख) में विनिर्दिष्ट किन्हीं वस्तुओं की, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिना किसी प्रकार के भ्रष्टाचार घटी लागत पर आपूर्ति करता है, भारत में किया गया कोई विक्रय नियम 7 के प्रयोजनों के लिए यूनिट मूल्य निश्चित करने में गणना में नहीं लिया जाना चाहिए।

6. इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियम 7(1) में निर्दिष्ट "लाभ और साधारण व्यय" संपूर्ण रूप में लिए जाने चाहिए। इस कटीती के प्रयोजन के लिए श्रंक का अवधारण आयातकर्ता द्वारा या उसकी ओर से प्रदाय की गई जानकारी के आधार पर किया जाना चाहिए जबतक कि उसके श्रंक उसी वर्ग या क्रम के आयातित माल के भारत में विक्रय से प्राप्त श्रंकों से असंगत न हों। जहाँ आयातकर्ता के श्रंक ऐसे श्रंकों से असंगत हैं वहाँ लाभ और साधारण व्यय के लिए रकम आयातकर्ता द्वारा या उसकी ओर से प्रदाय की गई जानकारी से बिना मृशंगत जानकारी पर आधारित हो सकती है।

7. साधारण व्ययों के अंतर्गत प्रस्तुत माल को विनिर्माण करने के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्च हैं।

8. ऐसे माल के जिसके लिए नियम 7(1)(iii) 5 उपबन्धों के अधीन कोई कटीती नहीं की गई है, विक्रय के कारण संबंध स्थायी करने की नियम 7(1) (i) के उपबन्धों के अधीन कटीती की जाएगी।

9. नियम 7(1) के उपबंधों के अधीन क्रमोक्तों का या सामान्य नामों तथा साधारण स्थलों का अवधारण करने में एवं इस प्रश्न का अवधारण कि कुछ माल "उसी वर्ग या किसम का" है जैसा अन्य माल है अन्तर्बलिष्ठ परिस्थितियों के प्रति निर्देश से मामला प्रति मामला के आधार पर किया जाना चाहिए। उसी वर्ग या किसम के आयातित माल के संकीर्णतम समूह या रेंज के भारत में विद्यमान होने के अन्तर्गत मूल्यांकित किया जाने वाला माल भी है जिसके लिए आवश्यक जानकारी की व्यवस्था की जा सकती है, परीक्षा की जाती चाहिए। नियम 7 के प्रयोजनों के लिए "उसी वर्ग का किसम का माल" के अन्तर्गत उसी देश से आयातित माल है जैसा कि मूल्यांकित किया जाने वाला और अन्य देश से आयात किया गया माल है।

10. नियम 7(2) के प्रयोजनों के लिए "नियमनकारी" यह तारीख होगी जिस तक आयातित माल का समस्त अवकाश बंद हो आयातित माल का विपणन सूनिष्ठ घोषित स्थापित करने के लिए पर्याप्त परिमाण में किया गया है।

11. जहाँ नियम 7(3) में पद्धति का उपयोग किया जाता है, वहाँ प्राप्ति की प्रक्रिया द्वारा जोड़े गए मूल्य के लिए जो गई कटौतियाँ ऐसे कार्य के खर्च से संबंधित यस्तुपक्ष और परीमाणीय शोकडों पर आधारित होंगी। स्वीकृत उद्योग सूत्र, युक्तियाँ मरकत की पद्धतियों और अन्य उद्योग पद्धतियाँ साधन का आधार होंगी।

12. यह संभवता प्राप्त है कि नियम 7(3) में उपबलिष्ठ मूल्यांकन की पद्धति साधारणतः वहाँ लागू नहीं होगी; अथ प्राप्ति की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आयातित माल अपनी पहचान खो देता है, तथापि ऐसे अवधारण हो सकते हैं जहाँ यद्यपि आयातित माल की पहचान खो गई है, किन्तु प्रक्रिया द्वारा जोड़े गए मूल्य का अयुक्तियुक्त कठिनाई के बिना सहो-सही अवधारण किया जा सकता है। दूसरी ओर ऐसे भी अवधारण हो सकते हैं जहाँ आयातित माल अपनी पहचान बनाए रखता है किन्तु आयात के देश में विक्रय किए गए माल में ऐसे छोटे तत्व बनाता है। कि इस मूल्यांकन पद्धति का प्रयोग व्यायसंगत नहीं होगा। उक्त की दृष्टि से इस किसम की प्रत्येक परिस्थिति पर मामला प्रति मामला के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

नियम 8 का टिप्पण.

1. नियम 8 के उपबंधों के अधीन अवधारित आयातित माल का मूल्य, अधिकतम संभव विस्तार तक, पहले से ही अवधारित सीमाशुल्क मूल्य पर आधारित होगा, चाहिए।

2. नियम 8 के अधीन निर्धारित की जाने वाली मूल्यांकन की पद्धतियाँ हो सकती हैं जो नियम 4 के नियम 7 तक में, इनकी सम्मिलित करने हुए, अविकथित हैं, किन्तु ऐसी पद्धतियों के लागू करने में युक्तियुक्त खोजलापन नियम 8 के उद्देश्यों और उपबंधों के अनुषंग होगा।

3. युक्तियुक्त लचीलेपन के कुछ उदाहरण यथा निम्नलिखित हैं :-

(क) समस्त माल—इस अपेक्षा का कि समस्त माल उसी समय पर या उसके लगभग जैसा कि मूल्यांकित किया जाने वाला माल है, आयातित होना चाहिए, लचीले रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है; मूल्यांकित किए जाने वाले माल के निर्यात के देश से अन्यथा देश में उत्पादित समस्त आयातित माल सीमाशुल्क मूल्यांकन के लिए आधार हो सकता है, नियम 7 के उपबंधों के अधीन पहले से ही अवधारित समस्त आयातित माल के सीमाशुल्क मूल्य का प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) वैसा ही माल—इस अपेक्षा का कि वैसा ही माल उसी समय पर या उसके लगभग आयातित किया जाना चाहिए जैसा कि मूल्यांकित किया जाने वाला माल है लचीले रूप से

निर्दिष्ट किया जा सकता है; मूल्यांकित किए जाने वाले माल के निर्यात के देश से भिन्न देश में उत्पादित वैसा ही आयातित माल सीमाशुल्क मूल्यांकन के लिए आधार हो सकता है; नियम 7 के उपबंध के अधीन पहले से ही अवधारित माल के सीमाशुल्क मूल्य का उपयोग किया जा सकता है।

(ग) नियमात्मक पद्धति—इस अपेक्षा का कि माल का नियम 7(1) में "उस देश में, जैसे आयात किया गया है" विक्रय किया गया होगा, लचीले रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है; "समस्त दिन" अपेक्षा को लचीले रूप से प्रमाणित प्रमाणित किया जा सकता है।

नियम 9 का टिप्पण

नियम 9(1) (क)(i) में "अथ कमीशन" पद से आयातकर्ता द्वारा मूल्यांकित किए जाने वाले माल रूप में विशेष में उसका प्रतिनिधित्व करने की सेवा के लिए उसके अधिकारी को सदन की गई फीन प्रतिभे है।

नियम 9(1) (ख) (ii)

1. आयातित माल के लिए नियम 9(1) (ख) (ii) में विनिर्दिष्ट तत्वों के प्रमाणन में दो बातें अन्तर्बलिष्ठ हैं तत्त्व का स्थान का मूल्य और वह रीति जिसमें वह मूल्य आयातित माल के लिए प्रमाणित किया जाना है। इन तत्वों का प्रमाणन उन परिस्थितियों के लिए समुचित युक्तियुक्त रीति में और साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण मित्राओं के अनुषंग किया जाना चाहिए।

2. तत्त्व के मूल्य के संबंध में, यदि आयातकर्ता किसी विज्ञेता से कोई तत्व, जो उससे संबंधित ही है, दिए हुए खर्च पर अर्जित करता है, तो इस तत्व का मूल्य वह खर्च है। यदि वह तत्व आयातकर्ता द्वारा या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित किया गया था तो उसका मूल्य उसे उत्पादित करने का खर्च होगा। यदि उस तत्व का आयातकर्ता द्वारा पहले ही उपयोग किया गया है तो इस बात का ध्यान रखने हुए कि वह ऐसे आयातकर्ता द्वारा अर्जित या उत्पादित किया गया था, अर्जन या उत्पादन का पूरा खर्च उस तत्व के मूल्य को प्राप्ति करने के लिए उसका उपयोग प्रतिनिधित्व करने के लिए समायोजित किया जाना होगा।

3. यदि एक बार उस तत्व के लिए मूल्य अवधारित हो गया है, तो उस मूल्य की आयातित माल के लिए प्रमाणित करना आवश्यक है। विभिन्न संभाव्यताएं विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए मूल्य पहले लदाई के लिए प्रमाणित किया जा सकता है यदि आयातकर्ता संपूर्ण मूल्य पर एक ही समय में शुल्क का संदाय करने की वांछा करता है। दूसरे उदाहरण के रूप में आयातकर्ता अनुरोध कर सकता है कि मूल्य प्रथम लदाई के समय तक उत्पादित यूनिटों की संख्या में प्रमाणित किया जाए। प्राप्ति उदाहरण के रूप में वह अनुरोध कर सकता है कि मूल्य संपूर्ण प्रत्यागित उत्पादन में जहाँ उस उत्पादन के लिए संबिदाये या कुछ प्रतिबद्धताएं विद्यमान हैं, प्रमाणित किया जाए। प्रयुक्त प्रमाणन की पद्धति आयातकर्ता द्वारा दिए गए दस्तावेजों पर निर्भर होगी।

4. उपरोक्त के उदाहरण के रूप में कोई आयातकर्ता उत्पादक के लिए आयातित माल के उत्पादन में प्रयुक्त सांचे की व्यवस्था करता है और उसके साथ, वस हजार यूनिटें क्रय करने की संविदा करता है। एक हजार यूनिटों की पहली लदाई के पहुंचने के समय तक उत्पादन पहले ही बार हजार यूनिटें उत्पादित कर लेता है। आयातकर्ता उचित सीमाशुल्क अधि-कारी से अनुरोध कर सकता है कि वह सांचे का मूल्य एक हजार यूनिटों बार हजार यूनिटों या वस हजार यूनिटों में प्रमाणित कर दे।

नियम 9(1)(ख)(iv)

1. नियम 9(1)(ख)(iv) में विनिर्दिष्ट तत्वों में परिवर्धन वस्तुपरक और परिमाण संबंधी आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए। जोड़े जाने वाले मूल्यों का अवधारण करने में आयातकर्ता और सीमाशुल्क के उचित अधिकारी दोनों के लिए भार कम करने की दृष्टि से केता की वाणिज्यिक अभिलेख पद्धति में उपलब्ध नैवार आंकड़ों का यथासंभव प्रयोग किया जाना चाहिए।

2. उन तत्वों के लिए, जिनका केता द्वारा प्रदाय किया गया है, जो केता द्वारा कय किए गए या पट्टे पर दिए गए हैं, जोड़ कय या पट्टे का खर्च होगा। उन तत्वों के लिए, जो जनता के परिक्षेत्र में उपलब्ध हैं, उनकी प्रतियां प्राप्त करने के खर्च वे भिन्न हैं, कोई परिवर्धन नहीं किया जाएगा।

3. वह सुविधा जिससे जोड़े जाने वाले मूल्यों की परिगणना करना समय संभव हो सकेगा, किसी विनिर्दिष्ट फर्म की संरचना और प्रबंध पद्धति तथा उसकी लेखाकरण पद्धतियों पर निर्भर करेगी।

4. उदाहरण के लिए यह संभव है कि कोई फर्म जो विभिन्न देशों से विभिन्न किस्मों के उत्पादों का आयात करती है, अपने डिजाइन केन्द्र का अभिलेख आयात के देश के बाहर ऐसे रूप में रखती हो जिससे कि किसी दिए हुए उत्पाद के प्रति खर्च को ठीक-ठीक दक्षित किया जा सके। ऐसे मामलों में नियम 9 के उपबंधों के अधीन प्रत्यक्ष समायोजन समुचित रूप से किया जा सकता है।

5. दूसरे मामले में कोई फर्म डिजाइन केन्द्र को खर्च को विनिर्दिष्ट उत्पादों को आबंटित किए बिना साधारण उपरिचय के रूप में आयात के देश के बाहर ले जा सकती है। डिजाइन केन्द्र से लाम उठाने वाले कुल उत्पादन में डिजाइन केन्द्र के कुल खर्चों का प्रभाजन करके और ऐसे प्रभाजित खर्च को यूनिट के आधार पर आयातों में जोड़कर आयातित माल के संबंध में नियम 9 के उपबंधों के अधीन समुचित समायोजन किया जा सकता है।

6. उक्त परिस्थितियों में विनिश्चिताएं आबंटन की उचित पद्धति का अवधारण करने में विचार किए जाने वाले विभिन्न तत्वों की अपेक्षा कर संकेती।

7. ऐसे मामलों में जहाँ प्रत्यक्ष तत्व का उत्पादन कई देशों को ऐसे अंतर्बलित करता है और किसी कालावधि में हुआ है, वहाँ समायोजन आयात के देश से बाहर इस तत्व में वास्तव में जोड़े गए मूल्य तक परि-सीमित होता चाहिए।

नियम 9 (1) (ग)

1. नियम 9 (1)(ग) में निविष्ट स्वामित्व और अनुज्ञप्ति कीम में अन्य बातों के साथ पेटेंटों, व्यापार चिन्हों और प्रतिलिप्याकारों के संबंध में संवाय सम्मिलित हो सकेंगे। तथापि आयात के देश में आयातित माल पुनरुत्पादित करने के अधिकार के लिए प्रभार सीमाशुल्क मूल्य का अवधारण करने में आयातित माल के लिए वास्तव में संदत्त की गई या संदेय कीमत में नहीं जोड़े जाएंगे।

2. आयातित माल का बितरण करने या पुनः विक्रय करने के अधिकार के लिए केता द्वारा किए गए संदाय आयातित माल के लिए वास्तव में संदत्त किए गए या संदेय कीमत में नहीं जोड़े जायेंगे यदि ऐसे संदाय आयातित माल के आयात वाले देश में निर्यात के लिए विक्रय की शर्तें नहीं हैं।

नियम 9(3)

जहाँ नियम 9 के उपबंधों के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित परिवर्धनों के संबंध में वस्तुपरक और परिमाण संबंधी आंकड़े विद्यमान नहीं

हैं, वहाँ संभवतः मूल्य का नियम 4 के उपबंधों के अधीन अवधारण नहीं किया जा सकता। इसके उदाहरण के रूप में स्वामित्व का संवाय कितो निविष्ट उत्पाद के, जिसका किनोपाम द्वारा आयात किया गया या और आयात के पक्वान् जैसे किसी चीज में बनाया गया था, आयात वाले देश में विक्रय में एक लीटर की कीमत के आधार पर किया जाता है। यदि स्वामित्व भागतः आयातित माल पर और भागतः ऐसे अन्य तत्वों पर आधारित है, जिनका आयातित माल से कोई संबंध नहीं है। जैसे जब आयातित माल देशीय संघटकों के साथ मिश्रित होता है और पृथक रूप से उसकी पहचान नहीं जा सकता या जब स्वामित्व केता और विक्रेता के बीच विशेष वित्तीय प्रबंध से सुनिश्च नहीं किया जा सकता। यह अनुचित होगा कि स्वामित्व के लिए परिवर्धन किए जाने के लिए कोई प्रयास किए जाएं। तथापि यदि स्वामित्व का एकम आयातित माल पर ही आधारित है और तुरन्त मुणित की जा सकती है तो वास्तव में संदत्त की गई या संदेय कीमत में परिवर्धन किया जा सकता है।

[फा. स. 523/167/88-सी.गु. (टी.यू.) आई.सी.डी.]

एम. नमिधरन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 1988

51-NT/88—CUSTOMS

G.S.R. 800(E).—In exercise of the powers conferred section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and in supersession of the Customs Valuation Rules, 1963 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules namely :—

1. Short title, commencement and application.—
(1) These rules may be called the Customs Valuation (Determination of price of Imported Goods) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the 16th August, 1988

(3) They shall apply to imported goods where a duty of customs is chargeable by reference to their value.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) “deductive value” means the value determined in accordance with rule 7 of these rules;

(b) “goods of the same class or kind”, means imported goods that are within a group or range of imported goods produced by a particular industry or industrial sector and includes indentical goods or similar goods;

(c) “identical goods” means imported goods—

(i) which are same in all respects, including physical characteristics, quality and reputation as the goods being valued except for minor differences in appearance that do not affect the value of the goods;

- (ii) produced in the country in which the goods being valued were produced; and
- (iii) produced by the same person who produced the goods, or where no such goods are available, goods produced by a different person,

but shall not include imported goods where engineering, development work, artwork, design work, plant or sketch undertaken in India were completed directly or indirectly by the buyer on these imported goods free of charge or at a reduced cost for use in connection with the production and sale for export of these imported goods;

- (d) "produced" includes grown, manufactured and mined;
- (e) "similar goods" means imported goods :—
 - (i) which although not alike in all respects, have like characteristics and like component materials which enable them to perform the same functions and to be commercially interchangeable with the goods being valued having regard to the quality, reputation and the existence of trademark;
 - (ii) produced in the country in which the goods being valued were produced; and
 - (iii) produced by the same person who produced the goods being valued, or where no such goods are available, goods produced by a different person,

but shall not include imported goods where engineering, development work, art work, design work, plan or sketch undertaken in India were completed directly or indirectly by the buyer on these imported goods free of charge or at a reduced cost for use in connection with the production and sale for export of these imported goods;

- (f) "transaction value" means the value determined in accordance with rule 4 of these rules.

(2) For the purpose of these rules, persons shall be deemed to be "related" only if —

- (i) they are officers or directors of one another's businesses;
- (ii) they are legally recognised partners in business;
- (iii) they are employer and employee;
- (iv) any person directly or indirectly owns, controls or holds 5 per cent or more of the outstanding voting stock or shares of both of them;
- (v) one of them directly or indirectly controls the other;
- (vi) both of them are directly or indirectly controlled by a third person;
- (vii) together they directly or indirectly control a third person; or

- (viii) they are members of the same family.

Explanation I.—The term "person" also includes legal persons.

Explanation II.—Persons who are associated in the business of one another in that one is the sole agent or sole distributor or sole concessionaire, however described, of the other shall be deemed to be related for the purpose of these rules, if they fall within the criteria of this sub-rule.

3. Determination of the method of valuation.—

For the purpose of these rules,—

- (i) the value of imported goods shall be the transaction value;
- (ii) if the value cannot be determined under the provisions of clause (i) above, the value shall be determined by proceeding sequentially through rule 5 to 8 of these rules.

4. Transaction Value—(1) The transaction value of imported goods shall be the price actually paid or payable for the goods when sold for export to India, adjusted in accordance with the provisions of rule 9 of these rules.

(2) The transaction value of imported goods under sub-rule (1) above shall be accepted; Provided that :—

- (a) there are no restrictions as to the disposition or use of the goods by the buyer other than restrictions which :—
 - (i) are imposed or required by law or by the public authorities in India; or
 - (ii) limit the geographical area in which the goods may be resold; or
 - (iii) do not substantially affect the value of the goods;
- (b) the sale or price is not subject to some condition or consideration for which a value cannot be determined in respect of the goods being valued;
- (c) no part of the proceeds of any subsequent resale, disposal or use of the goods by the buyer will accrue directly or indirectly to the seller, unless an appropriate adjustment can be made in accordance with the provisions of rule 9 of these rules; and
- (d) the buyer and seller are not related, or where the buyer and seller are related, that transaction value is acceptable for customs purposes under the provisions of sub-rule (3) below.

(3) (a) Where the buyer and seller are related, the transaction value shall be accepted provided that the examination of the circumstances of the sale of the imported goods indicate that the relationship did not influence the price.

(b) In a sale between related persons, the transaction value shall be accepted, whenever

the importer demonstrates that the declared value of the goods being valued, closely approximates to one of the following values ascertained at or about the same time :—

- (i) the transaction value of identical goods, or of similar goods, in sales to unrelated buyers in India;
- (ii) the deductive value for identical goods or similar goods :

Provided that in applying the values used for comparison, due account shall be taken of demonstrated difference in commercial levels, quantity levels, adjustments in accordance with the provisions of rule 9 of these rules and cost incurred by the seller in sales in which he and the buyer are not related;

- (c) substitute values shall not be established under the provisions of clause (b) of this sub-rule.

5. Transaction Value of Identical goods:—

- (1) (a) Subject to the provisions of rule 3 of these rules, the value of imported goods shall be the transaction value of identical goods sold for export to India and imported at or about the same time as the goods being valued.
- (b) In applying this rule, the transaction value of identical goods in a sale at the same commercial level and in substantially the same quantity as the goods being valued shall be used to determine the value of imported goods.
- (c) Where no sale referred to in clause (b) of sub-rule (1) of this rule, is found, the transaction value of identical goods sold at a different commercial level or in different quantities or both, adjusted to take account of the difference attributable to commercial level or to the quantity or both, shall be used, provided that such adjustments shall be made on the basis of demonstrated evidence which clearly establishes the reasonableness and accuracy of the adjustments leads to an increase or decrease in the value.

(2) Where the costs and charges referred to in sub-rule 2 of rule 9 of these rules are included in the transaction value of identical goods, in adjustment shall be made, if there are significant differences in such costs and charges between the goods being valued and the identical goods in question arising from differences in distances and means of transport.

(3) In applying this rule, if more than one transaction value of identical goods is found, the lowest such value shall be used to determine the value of imported goods.

6. Transaction value of similar goods.—(1) Subject to the provisions of rule 3 of these rules, the value of imported goods shall be the transaction

value of similar goods sold for export to India and imported at or about the same time as the goods being valued.

(2) The provisions of clauses (b) and (c) of sub-rule (1), sub-rule (2) and sub-rule (3), of rule 5 of these rules shall, *Mutatis mutandis*, also apply in respect of similar goods.

7. Deductive value.—(1) Subject to provisions of rule 3 of these rules, if the goods being valued or identical or similar imported goods are sold in India, in the condition as imported at or about the time at which the declaration for determination of value is presented, the value of imported goods shall be based on the unit price at which the imported goods or identical or similar imported goods are sold in the greatest aggregate quantity to persons who are not related to the sellers in India, subject to the following deductions :—

- (i) either the commission usually paid or agreed to be paid or the additions usually made for profits and general expenses in connection with sales in India of imported goods of the same class or kind;
- (ii) the usual costs of transport and insurance and associated costs incurred within India;
- (iii) the customs duties and other taxes payable in India by reason of importation or sale of the goods.

(2) If neither the imported goods nor identical nor similar imported goods are sold at or about the same time of importation of the goods being valued, the value of imported goods shall, subject otherwise to the provisions of sub-rule (1) of this rule, be based on the unit price at which the imported goods or identical or similar imported goods are sold in India, at the earliest date after importation but before the expiry of ninety days after such importation.

- (3) (a) If neither the imported goods nor identical nor similar imported goods are sold in India in the condition as imported, then, the value shall be based on the unit price at which the imported goods, after further processing, are sold in the greatest aggregate quantity to persons who are not related to the seller in India.
- (b) In such determination, due allowance shall be made for the value added by processing and the deductions provided for in items (i) to (iii) of sub-rule (1) of this rule.

8. Residual Method.—(1) Subject to the provisions of rule 3 of these rules, where the value of imported goods cannot be determined under the provisions of any of the preceding rules, the value shall be determined using reasonable means consistent with the principles and general provisions of these rules and sub-section (1) of section of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and on the basis of data available in India.

(2) No value shall be determined under the provisions of these rules on the basis of :—

- (i) the selling price in India of the goods produced in India;

- (ii) a system which provides for the acceptance for customs purposes of the highest of the two alternative values;
- (iii) the price of the goods on the domestic market of the country of exportation;
- (iv) the price of the goods for the export to a country other than India;
- (v) minimum customs values; or
- (vi) arbitrary or fictitious values.

9. Cost and Services—

(1) In determining the transaction value, there shall be added to the price actually paid or payable for the imported goods,—

- (a) the following cost and services, to the extent they are incurred by the buyer but are not included in the price actually paid or payable for the imported goods, namely :—
 - (i) Commissions and brokerage, except buying Commissions;
 - (ii) the cost of containers which are treated as being one for customs purposes with the goods in question;
 - (iii) the cost of packing whether for labour or materials;
- (b) the value, apportioned as appropriate, of the following goods and services where supplied directly or indirectly by the buyer free of charge or at reduced cost for use in connection with the production and sale for export of imported goods, to the extent that such value has not been included in the price actually paid or payable, namely :—
 - (i) materials, components, parts and similar items incorporated in the imported goods;
 - (ii) tools, dies, moulds and similar items used in the production of the imported goods;
 - (iii) materials consumed in the production of the imported goods;
 - (iv) engineering, development, art work, design work, and plans and sketches, undertaken elsewhere than in India and necessary for the production of the imported goods;
- (c) royalties and licence fees related to the imported goods that the buyer is required to pay, directly or indirectly, as a condition of the sale of the goods being valued, to the extent that such royalties and fees are not included in the price actually paid or payable;
- (d) the value of any part of the proceeds of any subsequent resale, disposal, or use of the imported goods that accrues, directly or indirectly, to the seller;
- (e) all other payments actually made or to be made as a condition of sale of the imported goods, by the buyer to the seller, or by the

buyer to a third party to satisfy an obligation of the seller to the extent that such payments are not included in the price actually paid or payable.

(2) For the purposes of sub-section (1) and sub-section (1A) of section 1 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and these rules, the value of the imported goods shall be the value of such goods, for delivery at the time and place of importation and shall include—

- (a) the cost of transport of the imported goods to the place of importation;
- (b) loading, unloading and handling charges associated with the delivery of the imported goods at the place of importation; and
- (c) the cost of insurance:

Provided that in the case of goods imported by air, the cost and charges referred to in clauses (a), (b) and (c) above,—

- (i) where such cost and charges are ascertainable, shall not exceed twenty per cent of the free on board value of such goods,
- (ii) where such cost and charges are not ascertainable such cost and charges shall be twenty per cent of the free on board value of such goods;

Provided further that in the case of goods imported other than by air and the actual cost and charges referred to in clauses (a), (b) and (c) above are not ascertainable, such cost and charges shall be twenty-five per cent of the free on board value of such goods.

- (3) Addition to the price actually paid or payable shall be made under this rule on the basis of objective and quantifiable data.
- (4) No addition shall be made to the price actually paid or payable in determining the value of the imported goods except as provided for in this rule.

10. Declaration by the importer.—(1) The importer or his agent shall furnish,—

- (a) a declaration disclosing full and accurate details relating to the value of imported goods; and
- (b) any other statement, information or document as considered necessary by the proper officer of customs for determination of the value of imported goods under these rules.

(2) Nothing contained in these rules shall be construed as restricting or calling into question the right of the proper officer of customs to satisfy himself as to the truth or accuracy of any statement, information, document or declaration presented for valuation purposes.

(3) The provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) relating to confiscation, penalty and prosecution shall apply to cases where wrong declaration, information, statement or documents are furnished under these rules;

11. Settlement of dispute.—In case of dispute between the importer and the proper officer of customs valuing the goods, the same shall be resolved consistent with the provisions contained in sub-section (1) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

12. Interpretative Notes :—The interpretative notes specified in the Schedule to these rules shall apply for the interpretation of these rules.

THE SCHEDULE

(See rule 12)

INTERPRETATIVE NOTES

General Note

Use of generally accepted accounting principles

1. "Generally accepted accounting principles" refers to the recognised consensus or substantial authoritative support within a country at a particular time as to which economic resources and obligations shall be recorded as assets and liabilities, which changes in assets and liabilities should be recorded, how the assets and liabilities and changes in them should be measured, what information should be disclosed and how it should be disclosed, and which financial statements should be prepared. These standards may be broad guidelines of general application as well as detailed practices and procedures.

Notes to rules

Note to rule 2

In rule 2(2)(v), for the purposes of these rules, one person shall be deemed to control another when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.

Note to rule 4

Price actually paid or payable

The price actually paid or payable is the total payment made or to be made by the buyer to or for the benefit of the seller for the imported goods. The payment need not necessarily take the form of a transfer of money. Payment may be made by way of letters of credit or negotiable instruments. Payment may be made directly or indirectly. An example of an indirect payment would be the settlement by the buyer, whether in whole or in part, of a debt owed by the seller.

Activities undertaken by the buyer on his own account, other than those for which an adjustment is provided in rule 9, are not considered to be an indirect payment to the seller, even though they might be regarded as of benefit to the seller. The costs of such activities shall not, therefore, be added to the price actually paid or payable in determining the value of imported goods.

The value of imported goods shall not include the following charges or costs, provided that they are

distinguished from the price actually paid or payable for the imported goods;

- (a) Charges for construction, erection, assembly, maintenance or technical assistance, undertaken after importation on, imported goods such as industrial plant, machinery or equipment;
- (b) The cost of transport after importation;
- (c) duties and taxes in India.

The price actually paid or payable refers to the price for the imported goods. Thus the flow of dividends or other payments from the buyer to the seller that do not relate to the imported goods are not part of the customs value.

Rule 4(2) (a) (iii)

Among restrictions which would not render a price actually paid or payable unacceptable are restrictions which do not substantially affect the value of the goods. An example of such restrictions would be the case where a seller requires a buyer of automobiles not to sell or exhibit them prior to a fixed date which represents the beginning of a model year.

Rule 4(2) (b)

If the sale or price is subject to some condition or consideration for which a value cannot be determined with respect to the goods being valued, the transaction value shall not be acceptable for customs purposes. Some examples of this include :

- (a) The seller establishes the price of the imported goods on condition that the buyer will also buy other goods in specified quantities;
- (b) the price of the imported goods is dependent upon the price or prices at which the buyer of the imported goods sells other goods to the seller of the imported goods;
- (c) the price is established on the basis of a form of payment extraneous to the imported goods, such as where the imported goods are semi-finished goods which have been provided by the seller on condition that he will receive a specified quantity of the finished goods.

However, conditions or considerations relating to the production or marketing of the imported goods shall not result in rejection of the transaction value. For example, the fact that the buyer furnishes the seller with engineering and plans undertaken in India shall not result in rejection of the transaction value for the purposes of rule 4. Likewise, if the buyer undertakes on his own account, even though by agreement with the seller, activities relating to the marketing of the imported goods, the value of these activities is not part of the value of imported goods nor shall such activities result in rejection of the transaction value.

Rule 4(3)

1. Rule 4 (3) (a) and rule 4 (3) (b) provide different means of establishing the acceptability of a transaction value.

2. Rule 4(3) (a) provides that where the buyer and the seller are related, the circumstances surrounding the sale shall be examined and the transaction value shall be accepted as the value of imported goods provided that the relationship did not influence the price. It is not intended that there should be an examination of the circumstances in all cases where the buyer and the seller are related. Such examination will only be required where there are doubts about the acceptability of the price. Where the proper officer of customs has no doubts about the acceptability of the price, it should be accepted without requesting further information from the importer. For example, the proper officer of customs may have previously examined the relationship, or he may already have detailed information concerning the buyer and the seller, and may already be satisfied from such examination or information that the relationship did not influence the price.

3. Where the proper officer of customs is unable to accept the transaction value without further inquiry, he should give the importer an opportunity to supply such further detailed information as may be necessary to enable him to examine the circumstances surrounding the sale. In this context, the proper officer of customs should be prepared to examine relevant aspects of the transaction, including the way in which the buyer and seller organized their commercial relations and the way in which the price in question was arrived at, in order to determine whether the relationship influenced the price. Where it can be shown that the buyer and seller although related under the provisions of rule 2(2), buy from and sell to each other as if they were not related, this would demonstrate that the price had not been influenced by the relationship. As an example of this, if the price had been settled in a manner consistent with the normal pricing practices of the industry in question or with the way the seller settles prices for sales to buyers who are not related to him, this would demonstrate that the price had not been influenced by the relationship. As a further example, where it is shown that the price is adequate to ensure recovery of all costs plus a profit which is representative of the firm's overall profit realized over a representative period of time (e.g. on an annual basis) in sales of goods of the same class or kind, this would demonstrate that the price had not been influenced.

4. Rule 4(3) (b) provides an opportunity for the importer to demonstrate that the transaction value closely approximates to a "test" value previously accepted by the proper officer of customs and is therefore acceptable under the provisions of rule 4. Where a test under rule 4(3) (b) is met, it is not necessary to examine the question of influence under rule 3(a). If the proper officer of customs has already sufficient information to be satisfied, without further detailed inquiries, that one of the tests provided in rule 4(3) (b) has been met, there is no reason for him to require the importer to demonstrate that the test can

be met. In rule 4(3) (b) the term "unrelated buyers" means buyers who are not related to the seller in any particular case.

Rule 4(3) (b)

A number of factors must be taken into consideration in determining whether one value "closely approximates" to another value. These factors include the nature of the imported goods, the nature of the industry itself, the season in which the goods are imported, and whether the difference in values is commercially significant. Since these factors may vary from case to case, it would be impossible to apply a uniform standard such as a fixed percentage, in each case. For example, a small difference in value in a case involving one type of goods could be unacceptable while a large difference in a case involving another type of goods might be acceptable in determining whether the transaction value closely approximates to the "test" values set forth in rule 4(3) (b).

Notes to rule 5

1. In applying rule 5, the proper officer of customs shall, wherever possible, use a sale of identical goods at the same commercial level and in substantially the same quantities as the goods being valued. Where no such sale is found, a sale of identical goods that takes place under any one of the following three conditions may be used :

- (a) a sale at the same commercial level but in different quantities;
- (b) a sale at a different commercial level but in substantially the same quantities; or
- (c) a sale at a different commercial level and in different quantities.

2. Having found a sale under any one of these three conditions adjustments will then be made, as the case may be, for;

- (a) quantity factors only;
- (b) commercial level factors only; or
- (c) both commercial level and quantity factors.

3. For the purposes of rule 5, the transaction value of identical imported goods means a value, adjusted as provided for in rule 5(F) (b) and (c) and rule 5(2), which has already been accepted under rule 4.

4. A condition for adjustment because of different commercial levels or different quantities is that such adjustment, whether it leads to an increase or a decrease in the value, be made only on the basis of demonstrated evidence that clearly establishes the reasonableness and accuracy of the adjustment, e.g. valid price lists containing prices referring to different levels or different quantities. As an example of this, if the imported goods being valued consist of a shipment of 10 units and the only identical imported goods for which a transaction value exists involved

a sale of 500 units, and it is recognized that the seller grants quantity discounts, the required adjustment may be accomplished by resorting to the seller's price list and using that price applicable to a sale of 10 units. This does not require that a sale had to have been made in quantities of 10 as long as the price list has been established as being bona fide through sales at other quantities. In the absence of such an objective measure, however, the determination of a value under the provisions of rule 5 is not appropriate.

Note to rule 6

1. In applying rule 6, the proper officer of customs shall, wherever possible, use a sale of similar goods at the same commercial level and is substantially the same quantities as the goods being valued. For the purpose of rule 6, the transaction value of similar imported goods means the value of imported goods, adjusted as provided for in rule 6(2) which has already been accepted under rule 4.

2. All other provisions contained in Note to rule 5 shall *mutatis mutandis* also apply in respect of similar goods.

Note to Rule 7

1. The term "unit price at which goods are sold in the greatest aggregate quantity" means the price at which the greatest number of units is sold in sales to persons who are not related to the persons from whom they buy such goods at the first commercial level after importation at which such sales take place.

2. As an example of this, goods are sold from a price list which grants favourable unit prices for purchases made in larger quantities.

Sale quantity	Unit price	Number of sales	Total quantity sold at each price
1—10 units	100	10 sales of 5 units 5 sales of 3 units	65
11—25 units	95	7 sales of 11 units	55
over 25 units	90	1 sale of 30 units 1 sale of 50 units	80

The greatest number of units sold at a price is 80, therefore, the unit price in the greatest aggregate quantity is 90.

3. As another example of this, two sales occur. In the first sale 500 units are sold at a price of 95 currency units each. In the second sale 400 units are sold at a price of 90 currency units each. In this example, the greatest number of units sold at a particular price is 500; therefore, the unit price in the greatest aggregate quantity is 95.

4. A third example would be the following situation where various quantities are sold at various prices.

(a) Sales

Sale quantity	Unit price
40 units	100
30 units	90
15 units	100
50 units	95
25 units	105
35 units	90
5 units	100

(b) Totals

Total quantity sold	Unit price
65	90
50	95
60	100
25	105

In this example, the greatest number of units sold at a particular price is 65; therefore, the unit price in the greatest aggregate quantity is 90.

5. Any sale in India, as described in paragraph 1 above to a person who supplies directly or indirectly free of charge or at reduced cost for use in connection with the production and sale for export of the imported goods any of the elements specified in rule 9 (1) (b), should not be taken into account in establishing the unit price for the purposes of rule 7.

6. It should be noted that "profit and general expenses" referred to in rule 7(1) should be taken as

a whole. The figure for the purposes of this deduction should be determined on the basis of information supplied by or on behalf of the importer unless his figures are inconsistent with those obtaining in sales in India, of imported goods of the same class or kind. Where the importer's figures are inconsistent with such figures, the amount for profit and general expenses may be based upon relevant information other than that supplied by or on behalf of the importer.

7. The "general expenses" include the direct and indirect costs of marketing the goods in question.

8. Local taxes payable by reason of the sale of the goods for which a deduction is not made under the provisions of rule 7 (1) (iii) shall be deducted under the provisions of rule 7 (1) (i).

9. In determining either the commissions or the usual profits and general expenses under the provisions of rule 7 (1), the question whether certain goods are "of the same class or kind" as other goods must be determined on a case-by-case basis by reference to the circumstances involved. Sales in India, of the narrowest group or range of imported goods of the same class or kind, which includes the goods being valued, for which the necessary information can be provided, should be examined. For the purposes of rule 7 "goods of the same class or kind" includes goods imported from the same country as the goods being valued as well as goods imported from other countries.

10. For the purposes of rule 7(2) the "earliest date" shall be the date by which sales of the imported goods or of identical or similar imported goods are made in sufficient quantity to establish the unit price.

11. Where the method in rule 7 (3) is used, deductions made for the value added by further processing shall be based on objective and quantifiable data relating to the cost of such work. Accepted industry formulas, recipes, methods of construction, and other industry practices would form the basis of the calculations.

12. It is recognized that the method of valuation provided for in rule 7(3) would normally not be applicable when, as a result of the further processing, the imported goods lose their identity. However there can be instances where, although the identity of the imported goods is lost, the value added by the processing can be determined accurately without unreasonable difficulty. On the other hand there can also be instances where the imported goods maintain their identity but form such a minor element in the goods sold in the country of importation that the use of this valuation method would be unjustified. In view of the above, each situation of this type must be considered on a case-by-case basis.

Note to rule 8

1. Value of imported goods determined under the provisions of rule 8 should, the greatest extent possible, be based on previously determined customs values.

2. The methods of valuation to be employed under rule 8 may be those laid down in rules 4 to 7, inclusive, but a reasonable flexibility in the application of such methods would be in conformity with the aims and provisions of rule 8.

3. Some examples of reasonable flexibility are as follows :

- (a) Identical goods.—The requirement that the identical goods should be imported at or about the same time as the goods being valued could be flexibly interpreted; identical imported goods produced in a country other than the country of exportation of the goods being valued could be the basis for customs valuation; customs values of identical imported goods already determined under the provisions of rule 7 could be used.
- (b) Similar goods.—The requirement that the similar goods should be imported at or about the same time as the goods being valued could be flexibly interpreted; similar imported goods produced in a country other than the country of exportation of the goods being valued could be the basis for customs valuation; customs values of similar imported goods already determined under the provisions of rule 7 could be used.
- (c) Deductive method.—The requirement that the goods shall have been sold in the "condition as imported" in rule 7 (1) could be flexibly interpreted the ninety days requirement could be administered flexibly.

Note to rule 9

In rule 9 (1) (a) (i), the term "buying commissions" means fees paid by an importer to his agent for the service of representing him abroad in the purchase of the goods being valued.

Rule 9 (1) (b) (ii)

1. There are two factors involved in the apportionment of the elements specified in rule 9 (1) (b)(ii) to the imported goods—the value of the element itself and the way in which that value is to be apportioned to the imported goods. The apportionment of these elements should be made in a reasonable manner appropriate to the circumstances and in accordance with generally accepted accounting principles.

2. Concerning the value of the element, if the importer acquires the element from a seller not related to him at a given cost, the value of the element is that cost. If the element was produced by the importer or by a person related to him, its value would be the cost of producing it. If the element had been previously used by the importer, regardless of whether it had been acquired or produced by such importer, the original cost of acquisition or production would have to be adjusted downward to reflect its use in order to arrive at the value of the element.

3. Once a value has been determined for the element it is necessary to apportion that value to the imported goods. Various possibilities exist. For example, the value might be apportioned to the first shipment if the importer wishes to pay duty on the entire value at one time. As another example, the importer may request that the value be apportioned over the number of units produced up to the time of the first shipment. As a further example, he may request that the value be apportioned over the entire anticipated production where contracts or firm commitments exist for that production. The method of apportionment used will depend upon the documentation provided by the importer.

4. As an illustration of the above, an importer provides the producer with a mould to be used in the production of the imported goods and contracts with him to buy 10,000 units. By the time of arrival of the first shipment of 1,000 units, the producer has already produced 4,000 units. The importer may request the proper officer of customs to apportion the value of the mould over 1,000 units, 4,000 units or 10,000 units.

Rule 9 (1) (1) (iv)

1. Additions for the elements specified in rule 9 (1) (b) (iv) should be based on objective and quantifiable data. In order to minimize the burden for both the importer and proper officer of customs in determining the value to be added, data readily available in the buyer's commercial record system should be used in so far as possible.

2. For those elements supplied by the buyer which were purchased or leased by the buyer, the addition would be the cost of the purchase or the lease. No addition shall be made for those elements available in the public domain, other than the cost of obtaining copies of them.

3. The case with which it may be possible to calculate the values to be added will depend on a particular firm's structure and management practice as well as its accounting methods.

4. For example, it is possible that a firm which imports a variety of products from several countries maintains the records of its design centre outside the country of importation in such a way as to show accurately the costs attributable to a given product. In such cases, a direct adjustment may appropriately be made under the provisions of rule 9.

5. In another case, a firm may carry the cost of the design centre outside the country of importation as a general overhead expense without allocation to specific products. In this instance, an appropriate adjustment could be made under the provisions of rule

9 with respect to the imported goods by apportioning total design centre costs over total production benefiting from the design centre and adding such apportioned cost on a unit basis to imports.

6. Variations in the above circumstances will, of course, require different factors to be considered in determining the proper method of allocation.

7. In cases where the production of the element in question involves a number of countries and over a period of time, the adjustment should be limited to the value actually added to that element outside the country of importation.

Rule 9 (1) (c)

1. The royalties and licence fees referred to in rule 9 (1) (c) may include among other things, payments in respects to patents, trademarks and copyrights. However, the charges for the right to reproduce the imported goods in the country of importation shall not be added to the price actually paid or payable for the imported goods in determining the customs value.

2. Payments made by the buyer for the right to distribute or resell the imported goods shall not be added to the price actually paid or payable for the imported goods if such payments are not a condition of the sale for export to the country of importation of the imported goods.

Rule 9 (3)

Where objective and quantifiable data do not exist with regard to the additions required to be made under the provisions of rule 9, the transaction value cannot be determined under the provisions of rule 4. As an illustration of this, a royalty is paid on the basis of the price in a sale in the importing country of a litre of a particular product that was imported by the kilogram and made up into a solution after importation. If the royalty is based partially on the imported goods and partially on other factors which have nothing to do with the imported goods (such as when the imported goods are mixed with domestic ingredients and are no longer separately identifiable, or when the royalty cannot be distinguished from special financial arrangements between the buyer and the seller), it would be inappropriate to attempt to make an addition for the royalty. However, if the amount of this royalty is based only on the imported goods and can be readily quantified, an addition to the price actually paid or payable can be made.

[No. F. 528/167/88-Cus. (IU) ICD]

N. SASIDHARAN, Dy. Secy.

